

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में आजु लखनऊ में भइल मंत्रिमण्डल के बइठकी में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-दुइ हजार छब्बीस के सथहीं तीस गो महत्वपूर्ण प्रस्तावन के मंजूरी दीहल गइल। एगो रिपोर्ट-

कैबिनेट बैठक के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी उनसठ हजार ग्राम सभाओं तक बस सेवा पहुंचाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में लगभग बारह हजार ग्राम सभाओं में बसें नहीं जा पा रही हैं, उन गांवों तक बस पहुंचाने का फैसला लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अट्ठाइस सीटों वाली छोटी बसें चलाई जायेंगी। श्री सिंह ने बताया कि अब ओला और ऊबर जैसी कम्पनियों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में पंजीकरण कराना होगा। परिवहन निगम एक ऐप भी बनायेगा, जिसमें ओला और ऊबर की गाड़ियों और उसके चालक की पूरी जानकारी होगी। कैबिनेट द्वारा स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी, जिसके अनुसार अब प्रापर्टी बेचने वालों की पहचान को खतौनी में देखा जायेगा। बिना माल्कियत की जांच किये बगैर अब स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। राजस्व मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि सर्किल रेट के आधार पर ही स्टाम्प शुल्क लगेगा। समाचार कक्ष से प्रेम चन्द्र गुप्ता।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क प्रतिनिधिमण्डल आजु लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकाति कइ के केन्द्र सरकार की ओर से जारी एयरोड्रम लाइसेंस प्रस्तुत कइलस। एयरपोर्ट क मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टोफ श्नेलमैन के सथहीं सीनियर अधिकारियन क ई प्रतिनिधिमण्डल मुलाकाति के दौरान मुख्यमंत्री के परियोजनन के प्रगति आ आवे वाला फेरन के बारे में जनकारी दिहले।

पश्चिम एशिया में मौजूदा हालति के देखत सरकार प्राथमिकता वाला क्षेत्रन बदे प्राकृतिक गैस के उत्पादन के विनियमित कइले, आपूर्ति बनावल रखले, समान वितरण आ उपलब्धता सुनिश्चित करे बदे जरूरी वस्तु अधिनियम-ओन्नइस सौ पचपन लागू कइले हौ। एगो रिपोर्ट-

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार घरेलू पाइपलाइन प्राकृतिक गैस आपूर्ति, परिवहन के लिए सीएनजी, एलपीजी उत्पादन, पाइपलाइन कंप्रेसर ईंधन और अन्य आवश्यक पाइपलाइन परिचालन आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में प्राथमिकता दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि आपूर्ति को पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत के 100 प्रतिशत परिचालन उपलब्धता के अधीन बनाए रखा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि उर्वरक संयंत्रों को पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत के 70 प्रतिशत के बराबर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। गैस विपणन संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि राष्ट्रीय गैस ग्रिड के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले चाय उद्योग, विनिर्माण और अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत के 80 प्रतिशत के बराबर गैस की आपूर्ति बनी रहे। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी शहरी गैस वितरण संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जाने वाली गैस उनकी पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत का 80 प्रतिशत हो। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।

सूचना आ प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहलें कि भारत क रचनात्मक अर्थव्यवस्था क्षेत्र दुनिया खातिर देस क संस्कृति, खाद्य आ सोझै स्थानीय बिक्रेता लोगिन चाहे आस-पास के उत्पादकन से मिले वाला ताजा समानन क परदरसन कइ रहल बा। उहां के सबका साथ, सबका विकास-जनता के आकांक्षाओं की पूर्ति बिसय पर आयोजित बजट के बाद वेबिनार में ई बाति कहलीं। श्री वैष्णव कहलें कि प्रौद्योगिकी मीडिया मनोरंजन के क्षेत्र में खास भूमिका निभा रहलि हौ।

जो एंटरटेनमेंट और मीडिया की दुनिया है इस दुनिया में टेक्नोलॉजी का जो उपयोग अब इसको नैक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इसका पहला कैम्पस मुंबई में बन रहा है। इस टेंपरेरी कैम्पस में जो फैसिलिटीज बनीं जो ये ऐसे इंस्टीट्यूशनल चेन्स हैं, जो कि हमारे देश के युवाओं को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देती हैं, जहां से स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ सकें और एकदम रेलीवेंट फील्ड में वो अपने को एक्सपर्ट बना के मार्केट में, दुनिया में अपनी पहचान बना सकें।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आवे वाला सब-इंस्पेक्टर-सिविल पुलिस आ समकक्ष पदन बदे आयोजित होखे वाला सीधी भरती-दुइ हजार पचीस के लिखित परीक्षा कै निस्पक्षता बनावे रखे बदे लोगिन खातिर एगो समरपित ई-मेल आईडी आ व्हाट्सएप नम्बर जारी कइले हौ। बोर्ड के मोताबिक परीक्षा से जुड़ल कउनाहूँ संदिग्ध गतिविधि के लोगि ई-मेल आईडी सतर्कता डॉट पुलिसबोर्ड एट दी रेट जीमेल डॉट कॉम आ वाट्स एप नंबर नौ चारि पांच चारि पांच सात नौ पांच एक पर साझा कइ सके लें।
